आजादी के अमृत महोत्सव पर

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना!

भूमिका

फ्रैंक हुजूर

लेखक

एच.एल. दुसाध

आजादी के अमृत महोत्सव पर

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना!

एच. एल. दुसाध

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन
नई दिल्ली-110070

प्रथम संस्करण : अगस्त 2022

प्रकाशक : **बहुजन डाइवर्सिटी मिशन**
बी-1, 149/9, किशन गढ़, बसंत कुंज
नयी दिल्ली-110070
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. 011-26125979, 9654816191

© **लेखक**

मूल्य : 100.00 रुपये

रचना : बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना!
लेखक : एच. एल. दुसाध
आवरण : शिवम सागर
मुद्रक : लकी ऑफसेट, दिल्ली-110032

समर्पण

आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका
फातिमा शेख को, जिन्होंने महामना फुले और
उनकी जीवन संगिनी माता सावित्री बाई फुले
के साथ मिलकर वंचितों की शिक्षा के
क्षेत्र में महान योगदान किया!

अनुक्रम

भूमिका 7

लेखकीय 13

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना! 27

स्वाधीनता के 75 वर्ष–27, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में भारत!–29, आर्थिक और सामाजिक विषमता का सर्वाधिक शिकार : आधी आबादी!–29, गरीबी की राजधानी : भारत!–30, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर की चेतावनी!–31, नक्सली 2050 के पहले ही सरकार को उखाड़ फेकेंगे!–32, हमारा शासक वर्ग क्या स्वभावतः लोकतंत्र विरोधी रहा!–33, आर्थिक-सामाजिक विषमता की उत्पत्ति के पीछे : शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता की अनदेखी–34, भारत में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतीकात्मक प्रतिबिम्बन–35, वोट खरीदने के लिए राहत और भीखनुमा घोषणाओं पर निर्भर : हमारे राजनीतिक दल–35, बीडीएम के दस सूत्रीय एजेंडे से मिल सकता है चमत्कारिक परिणाम!–36, आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे लिए : विश्व असमानता रिपोर्ट-2022 का सुझाव!–37, नॉर्डिक मॉडल के बजाय बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा अपनाना क्यों है जरुरी!–38, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के डाइवर्सिटी मॉडल से प्रेरित है : बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा!–40, पार्टियों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी!–42, डाइवर्सिटी केन्द्रित मुद्दे से बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन!–43, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में विविधता नीति का कमाल!–44, भारत में डाइवर्सिटी आन्दोलन!–48, शुरू हो सकता है प्रतिक्रयावादी और प्रतिरोधात्मक आन्दोलन!–49, आधी आबादी की आर्थिक असमानता के खात्मे को ध्यान में रखकर बने : आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे की योजना!–51, आर्थिक विषमता का सर्वाधिक शिकारः दलित-आदिवासी समुदाय की महिलाएं!–52, 257 वर्षों के बजाय आगामी कुछ दशकों में : लैंगिक समानता पाने के दो खास उपाय!–53, भ्रष्टाचार को न्यूनतम

करने के लिए : डाइवर्सिटी!—55, संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए : डाइवर्सिटी—56, सच्चर रिपोर्ट में उभरी मुस्लिम समुदाय की बदहाली की तस्वीर को खुशहाली में बदलने के लिए : डाइवर्सिटी—58, आरक्षण से उपजते गृहयुद्ध के हालात से निजात पाने के लिए : डाइवर्सिटी—58, नक्सलवाद के शमन के लिए : डाइवर्सिटी—59, हिन्दुओं के अत्याचार से दलितों को बचाने के लिए : डाइवर्सिटी!—59, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रोकने के लिए : डाइवर्सिटी—60, हिंदुत्ववादी नयी शिक्षा नीति की काट के लिए : डाइवर्सिटी—61, विविधता में एकता को सार्थकता प्रदान करने के लिए : डाइवर्सिटी—63, ब्राह्मणशाही के खात्मे के लिए : डाइवर्सिटी—63, सौ रोगों की एक दवा : डाइवर्सिटी!—64, कैसे लागू होगा बीडीएम का डाइवर्सिटी एजेंडा!—65, बहुजनवादी दलों से कितनी उम्मीद!—66, मर सी गयी है बहुजनवादी दलों में सत्ता हासिल करने की इच्छाशक्ति—68, जनता के जरिये सरकारों पर बनाया जाय : बीडीएम के एजेंडे को लागू करवाने का दबाव!—70, हस्ताक्षर अभियान : आन्दोलन का सबसे प्रभावी व शांतिपूर्ण माध्यम!—71

परिशिष्ट : मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या से पार पाने के लिए : क्यों चलायें हस्ताक्षर अभियान! **72**

हस्ताक्षर अभियान की संभावनाएं!—75, हस्ताक्षरकर्ता ही बनंगे फंड का स्रोत और वोटर!—77, हस्ताक्षर अभियान के जरिये पैदा हो सकते है 10 हजार पेड वर्कर!—77, हस्ताक्षर अभियान के जरिये हम राजनीति के डिजिटलीकरण के मामले में सबको मीलों पीछे छोड़ देंगे!—78

भूमिका

यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट : बहुजन मुक्ति की बेमिसाल परिकल्पना!

–फ्रैंक हुजूर

उत्तर आधुनिक भारतीय नॉन-फिक्शन साहित्य रचना में डाइवर्सिटी मैन एच.एल. दुसाध का कोई मुक़ाबला नहीं है। दुसाध ने बीते ढाई दशकों में सबाल्टर्न सियासी और सांस्कृतिक लिटरेचर की जो हार्वेस्ट भारतीय और वैश्विक समाज को उपहार में दिया है, उसके लिए सदियों तक ना सिर्फ बहुजन कम्युनिटी बल्कि वह हर तबका उनका दिल की गहराइयों से आभारी रहेगा, जो अपने देश और लोगबाग को आर्थिक रूप से सुदृढ और राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से आज़ाद देखना चाहता है।

मेरी नज़र में दुसाध के विचार समकालीन भारत के अंग्रेजी में लिखने वाले रामचंद्र गुहा और प्रताप भानु मेहता जैसे भद्रलोक से भी अनमोल है। भारी वजन रखती हैं दुसाध के डाइवर्सिटी मिशन की थ्योरियां और उनके हिमालय पहाड़ जैसे भीमकाय जूनून का तो शायद कोई उफान मारता समंदर ही सामना कर सकता है।

मैंने उनके आत्मविश्वास को अटलांटिक महासागर जैसा गहरा पाया है। हर सुबह और शाम देश विदेश के ज्वलंत मुद्दों पर दुसाध को डेजर्ट स्टॉर्म की माफिक एंग्री और एजीटेटेड देखा है। भारतीय कुलीन जातिवादी मीडिया के धुरंधरों को दुसाध ने आर पार पब्लिक डिबेट के लिए दर्जनों बार ललकारा है, मगर चाहे वो रवीश कुमार हो या रजत शर्मा या अजित अंजुम, किसी भी 'सो-कॉल्ड लिबरल या दक्षिणपंथी मीडिया पर्सोनाल्टी में दुसाध जैसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल से लड़ने की इच्छाशक्ति में घनघोर कमी देखी गयी है। दुसाध को मैं दिलीप मंडल के साथ भारत का चोम्स्की या फिर कहे तो कैटलीन जोंस्टन मानता हूँ।

इस बहुप्रतीक्षित किताब के माध्यम से डाइवर्सिटी पुरुष दुसाध 'यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट' जैसे राजनीतिक सिद्धांत से एक नए माउंट एवेरेस्ट को फतह कर रहे हैं। अगर यूआरएफ को किसी भी सत्ताधारी दल ने जनता को समर्पित कर लागू कर दिया, तब भारत में एक शानदार वेलफेयर और इक्वलिटी सोसाइटी का सपना साकार हो जाएगा

जो वर्षों से बुद्ध, कबीर, फुले, आंबेडकर, लोहिया, सावित्री बाई और ना जाने कितने अनगिनत सोशल क्रांतिकारियों के दिलों में धधकती रही है और जिसकी चिंगारी यूरोप के फ्रांस में कभी गिरी तो कभी लैटिन अमेरिका के बोलीविया में तो कभी अफ्रीका के तुनिशिया या एशिया के मलेशिया में। भारत जैसी बेपनाह आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी की भुरभुरी ज़मीन पर ये चिंगारी डाइवर्सिटी पुरुष दुसाध लेकर आएं है : स्वागत करें इस महानायक की नयी रचना का!

दुसाध की नई पुस्तक का सार!

आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर डाइवर्सिटी मैन ऑफ़ इंडिया के रूप में मशहूर एच.एल. दुसाध द्वारा लिखी गयी यह किताब आजादी के बाद के 75 सालों का लेखा-जोखा पेश करते हुए बताती है–

–कि जिस तरह प्राचीन भारत में देवासुर संग्राम के बाद अमृत का घड़ा देवताओं और विष मूलनिवासियों को मिला, कुछ वैसी ही स्थिति आजादी के बाद के 75 सालों में रही। इन 75 सालों में दलित, आदिवासी,पिछड़े और इनसे धर्मान्तरित अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को आजादी का नाम मात्र ही अमृत मिला।(पेज 16);

–कि आज देश के नीचे की 50 -60 प्रतिशत आबादी महज 5-6 प्रतिशत नेशनल वेल्थ पर गुजर- बसर करने के लिए मजबूर है। लैंगिक समानता के मोर्चे पर देश दक्षिण एशिया में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से भी पीछे चला गया है और भारत में आधी आबादी को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर आने में 257 साल लगने हैं। आज भारत नाइजेरिया को पीछे धकेल कर विश्व गरीबी की राजधानी (world poverty caipital) का ख़िताब पा चुका है, जबकि घटिया शिक्षा के मामले में मलावी नामक एक अनाम देश को छोड़कर टॉप पर पहुँच गया है (पेज 31-33);

–कि देश की जिस विशाल आबादी को औसतन 6 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति पर गुजारा करना पड़ रहा है; जिस समुदाय की आधी आबादी को आर्थिक रूप से मर्दों के बराबर आने में 250-300 साल लगने हैं; जिनकी गरीबी के कारण ही भारत गरीबी में विश्व की राजधानी का ख़िताब पाया है और जिनके बच्चे वर्ल्ड टॉप घटिया शिक्षा के शिकार हैं, वह और कोई नहीं : दलित, आदिवासी, पिछड़ा और इनसे धर्मान्तरित लोगों से युक्त बहुजन समाज है (पेज-16);

–कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि आजाद भारत के शासकों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के 25 नवम्बर, 1949 वाले उस सुझाव, जिसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के हित में जल्द से जल्द आर्थिक और सामाजिक विषमता को ख़त्म कर लेने की बात कही थी, की बुरी तरह अनदेखी कर दिया। वे स्वभावतः लोकतंत्र विरोधी थे। अगर लोकतंत्र-प्रेमी होते तो केंद्र से लेकर राज्यों तक में काबिज हर सरकारों की कर्मसूचियां आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे पर केन्द्रित होतीं। तब आर्थिक

और सामाजिक विषमता का वह भयावह मंजर मंजर हमारे सामने नहीं होता, जिसके कारण आज हमारा लोकतंत्र विस्फोटित होने की ओर अग्रसर है तथा दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का जीवन नरक बना हुआ है : वे आजादी से निकले अमृत की एक-एक बूँद के लिए तरस रहे हैं (पेज 34-35);

—कि आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे लायक ठोस कदम न उठाने के बावजूद आजाद भारत के शासक 7 अगस्त, 1990 के पूर्व तक स्वाधीनता संग्राम के वादों को ध्यान में रखते हुए भारत के जन्मजात वंचितों के प्रति कुछ-कुछ सदय बने रहे, इसलिए संविधानगत कुछ-कुछ अधिकार देकर प्रतीकात्मक ही सही शक्ति के स्रोतों में कुछ-कुछ अवसर देते रहे। इस तरह आजादी से निकली अमृत की कुछ बूंदे वंचित बहुजनों को भी नसीब होती रहीं, किन्तु मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित के अगले दिन से वंचित बहुजनों के प्रति उनकी करुणा, शत्रुता में बदल गयी और वे वर्ग संघर्ष का इकतरफा खेल खेलते हुए आरक्षण के खात्मे और संविधान को व्यर्थ करने में जूनून के साथ जुट गए (पेज-17)।

—कि बहुजनों को संवैधानिक अवसरों से महरूम करने के लिए सबसे पहले नरसिंह राव ने 24 जुलाई, 1991 को अंगीकार किया नवउदरवादी अर्थनीति, जिसे आगे बढाने में उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह ने भी कोई कमी नहीं की। किन्तु, इस मामले में किसी ने सबको बौना बनाया तो वह रहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! जिस नवउदारवादी नीति की शुरुआत नरसिंह राव ने किया एवं जिसे भयानक हथियार के रूप इस्तेमाल किया प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने, उसके फलस्वरूप शक्ति के स्रोतों पर भारत के जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग आज जैसा दबदबा कायम हुआ है, उसकी मिसाल सम्पूर्ण विश्व इतिहास में मिलनी मुश्किल है! शक्ति के स्रोतों पर बेहिसाब कब्ज़ा जमाया भारत का वही जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग ही जूनून के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटा हुआ है। यही वर्ग ही सौ-सौ, दो-दो सौ फुट लम्बा झंडा फहरा रहा है : यही इस अवसर पर नारे लिख रहा है, यही अपने घरों की बालकनी तिरंगे से सजा रहा है (पेज-19);

—कि मंडल उत्तरकाल में नरसिंह राव की नवउदारीकरण अर्थनीति को हथियार बनाकर जिस तरह मोदी ने जूनून के साथ वर्ग-संघर्ष का इकतरफा खेल खेलते हुए निजीकरण, विनिवेशीकरण और लैटरल इंट्री के जरिये सारा कुछ जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग के देने का अभियान चलाया, उसके फलस्वरूप सुविधाभोगी वर्ग का शक्ति के तमाम स्रोतों-आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक इत्यादि—पर 80-90 प्रतिशत कब्ज़ा हो गया है। आजादी के 75वें साल का सिंहावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि मंडल उत्तरकाल में इसके अमृत का प्रायः सारा का सारा हिस्सा, इस देश के जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग के हिस्से में चला गया। आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश में भारत के परम्परागत विशेषाधिकारयुक्त व सुविधाभोगी वर्ग का जैसा शक्ति के स्रोतों पर दबदबा नहीं है।

इस दबदबे ने दलित, आदिवासी, पिछड़े और इनसे धर्मान्तरित बहुसंख्य लोगों के समक्ष जैसे विकट हालात पैदा कर दिए हैं, ऐसे से ही हालातों में भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्वाधीनता संग्राम संगठित हुए! अतः आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में मस्त है, तब इस अवसर पर अपनी आज़ादी की लड़ाई में उतरने का संकल्प लेने से भिन्न कोई हमारे समक्ष कोई विकल्प ही नहीं बचा है! हमारी आजादी की यह लड़ाई आजादी की सौवीं जयंती : 2047 तक दलित/ आदिवासी, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यकों और सवर्णों के स्त्री-पुरुषों के मध्य शक्ति के स्रोतों के वाजिब बंटवारे के लिए होगी। इसके लिए हम आजादी के 76 वें साल से वाजिब मात्रा में आजादी का अमृत बहुजनों के मध्य वितरित करने की योजना पर काम करने का संकल्प लेते हैं! (पेज-24)

–कि आजादी की सौवीं वर्षगांठ अर्थात 2047 तक बहुजनों की आजादी की रूप-रेखा पेश करते हुए यह किताब बताती है कि अगले 25 वर्षों तक हम 'यूनिवर्सल रिजर्वेशन' अर्थात सर्वव्यापी आरक्षण अर्थात चप्पे-चप्पे पर आरक्षण की लड़ाई लड़ने पर अपनी आजादी की लड़ाई का एजेंडा स्थिर करेंगे। सर्वव्यापी अर्थात यूनिवर्सल रिजर्वेशन पर अपनी आजादी की लड़ाई को इसलिए स्थिर करेंगे, क्योंकि दुनिया में जहां-जहां भी गुलामों ने शासकों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी शुरुआत आरक्षण से हुई,जिसकी सबसे उज्ज्वल मिसाल भारत का स्वाधीनता संग्राम है। अंग्रेजी शासन में शक्ति के समस्त स्रोतों पर अंग्रेजों के एकाधिकार दौर में भारत के प्रभुवर्ग के लड़ाई की शुरुआत आरक्षण की विनम्र मांग से हुई। एक बार आरक्षण का स्वाद चखने के बाद गुलाम भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वाधीनता का संग्राम छेड़ दिया (पेज-24)। आरक्षण पर आजादी की लड़ाई को केन्द्रित करने के पीछे दूसरा लॉजिक खड़ा करते हुए किताब कहती है कि चूंकि भारत में वर्ग-संघर्ष का इतिहास आरक्षण पर केन्द्रित संघर्ष का इतिहास रहा है, इसीलिए जब अगस्त 1990 में मंडल की रिपोर्ट आरक्षण का विस्तार हुआ, भारत का शासक वर्ग आरक्षण के खात्में में जुट गया और राजसत्ता का अधिकतम इस्तेमाल आरक्षण के खात्मे में करते हुए बहुजनों को गुलामों की स्थिति में पहुंचा दिया। ऐसे में हमें अपनी लड़ाई को बाकी बातें छोड़कर पूरी तरह यूनिवर्सल रिजर्वेशन पर केन्द्रित करनी होगी (पेज-19-23)। सर्वव्यापी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए यह किताब 'यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट' बनाने की घोषणा करते हुए करते हुए कहती है कि जिस तरह जहर की काट जहर से होती है, उसी तरह हमारे सामने बहुजनों की मुक्ति की लडाई को नए सिरे से आरक्षण पर केन्द्रित करने से भिन्न और कोई उपाय नहीं है। चूँकि यह लड़ाई वर्तमान सत्ताधारी दल के खिलाफ अकेले लड़ना कठिन है, इसलिए हम कई दलों/संगठनों को लेकर 'यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट' बनाने जा रहे हैं (पेज-25);

–कि चूँकि यूनिवर्सल रिजर्वेशन अर्थात सर्वव्यापी आरक्षण का सर्वोत्तम सूत्र बहुजन

डाइवर्सिटी मिशन के दस सूत्रीय एजेंडे में उभरकर आया है, जिसका विस्तृत व्योरा इस किताब में दिया गया है, इसलिए यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट बीडीएम के एजेंडे को लागू करवाने में सर्वशक्ति लगाएगा! इस फ्रंट के आजादी की लड़ाई के दायरे में सर्वव्यापी आरक्षण तो प्रमुखता से रहेगा ही रहेगा : साथ में होगा औने-पौने दामों में बेचीं गयी सरकारी संपत्तियों की समीक्षा तथा प्रयोजन पड़ने पर इनका राष्ट्रीयकरण; गरीब सवर्णों के आरक्षण के साथ नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का खात्मा; साथ में अग्निवीर, लैटरल इंट्री इत्यादि जैसी उन तमाम योजनाओं का खात्मा, जिनके जरिये मोदी-राज में आरक्षण के खात्मे तथा बहुजनों को शक्ति के स्रोतों से दूर धकेलने की साजिश अंजाम दी गयी है :

–कि सर्वव्यापी आरक्षण मोर्चा शक्ति के स्रोतों के वाजिब बंटवारे के लिए दो खास उपाय करेगा : सबसे पहले अवसरों के बंटवारे में भारत के सुविधाभोगी वर्ग के पुरुषों को उनके संख्यानुपात पर रोकेगा ताकि उनके हिस्से का 60-75 प्रतिशत अतिरिक्त (Surplus) अवसर का मूलनिवासी वंचित समाज के स्त्री-पुरुषों के मध्य बंटने का मार्ग प्रशस्त हो सके। दूसरा, हम अवसरों के बंटवारे में रिवर्स प्रणाली लागू करते हुए सबसे पहले क्रमशः एससी/एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को संख्यानुपात में अवसर देगे और बचा हुआ शेष भाग जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग के पुरुषों को देंगे! (पेज-26);

–कि यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट की परिकल्पना उस 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन' से जुड़े लेखकों के जेहन से उभरी है, जिस बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का दस सूत्रीय एजेंडा भारत में सौ रोगों की दवा है (पेज-69) एवं आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे में जिसकी प्रभावकारिता 'विश्व असमानता रिपोर्ट- 2022' में सुझाये 'नॉर्डिक इकॉनोमिक मॉडल' से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है (पेज-40-43)। इस फ्रंट में बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की भूमिका पर रौशनी डालते हुए कहा गया है,' इस मोर्चे में बीडीएम की भूमिका समन्वयक/संयोजक (को-ऑर्डिनेटर) की होगी। इससे जुड़े लेखक मोर्चे में शामिल दलों के लिए लेख लिखेंगे, चुनावों में जाकर प्रचार करेंगे और हस्ताक्षर अभियान की 60 प्रतिशत धनराशि इन्हें देकर इनकी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने में योगदान करेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास देश की आधी आबादी को 257 सालों के बजाय 57 सालों में पुरुषों के बराबर लाने के जरिये देश को मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या (आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी) से निजात दिलाने का जो सपना है, वह मोर्चे में शामिल दलों के जरिये जमीन पर उतारेंगे' (पेज-79);

–कि बहुजन डाइवर्सिटी मिशन आगामी 25 वर्षों तक बहुजन मुक्ति की लड़ाई में जागरूक बहुजनों को शामिल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। बीडीएम आजादी की लड़ाई में बाबा साहेब के इस कथन-*गुलामों को गुलामी का अहसास करा दो, वे गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे*–को मूलमंत्र बनाकर हस्ताक्षर करने वाले कोटि-कोटि

बहुजनों को 2,000 रूपये मूल्य की एक दर्जन से अधिक किताबें उनके मोबाइल में पीडीएफ़ में सुलभ कराएगा (पेज-75) और विनिमय में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए उनसे मात्र 50 रूपये की सहयोग राशि लेगा। (पेज- 76)। इसी हस्ताक्षर अभियान के जरिये बीडीएम यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट के लिए 10 हजार पेड़ वर्कर तैयार करेगा (पेज-77)। हस्ताक्षरकर्ता ही इस फ्रंट के लिए फण्ड का स्रोत और वोटर बनेंगे (पेज-77);

—कि आज यूरोप, अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण हो गया है। भारत में भी कुछ-कुछ हुआ है, किन्तु इसकी मुकम्मल शुरुआत बीडीएम के हस्ताक्षर अभियान से होगी। हस्ताक्षर अभियान की पूरी प्लानिंग डिजिटलीकरण पर निर्भर है। इस अभियान में फ्रंट से जुड़े दलों को अपनी बात जनता तक पहुचाने के लिए हजारों-लाखों की न तो भीड़ की जरुरत पड़ेगी और न धरना-प्रदर्शन की (पेज-78)। इसके लिए हमें हर जिले में 15-20 पूर्णकालिक पेड कार्यकर्त्ताओं की जरूरत पड़ेगी, जो लोगों के बीच जाकर हस्ताक्षर लेंगे और बाकी काम हमारी तकनीकी टीम ऑफिस में बैठे-बैठे कर लेगी। फ्रंट में शामिल हमारे नेता भी ऑफिस में बैठे-बैठे बेबीनॉर के जरिये रोज देश के कई जिले के लोगों/कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहेंगे। रोजाना उनके वीडियो तकनीकी टीम के सहारे लाखों/करोड़ों हस्ताक्षरदाताओं तक पहुंचा करेगा। इस तरह भारत में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के मोर्चे पर हम अन्य दलों से बहुत आगे रहेंगे;

—कि अगर राजनीति में सफल होने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी है तो यह काम हस्ताक्षर अभियान के जरिये कम समय और कम साधन में परम्परागत स्थापित दलों से बेहतर कर पाएंगे (पेज-78)। अंत में इस किताब के लेखक दुसाध जोर गले से घोषणा करते हैं कि *'बीडीएम जैसा हस्ताक्षर अभियान चलाने की कूवत भारत के किसी दल या संगठन में है ही नहीं। न किसी के पास इस देश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी को प्रभावित करने लायक हमारे जैसा एजेंडा है और न ही एजेंडे से करोड़ों लोगों को अवगत कराने लायक विपुल साहित्य। इसलिए हमारे अभियान की कोई चाहकर भी नक़ल नहीं कर सकता (पेज-79)!*

उपरोक्त सूचनाओं को ही किताब में विस्तार के साथ परोसा गया है। आखिर में मैं इस किताब के विषय में तीन खास बातें बताना चाहूंगा!

1. *महिलाओं के एंपावरमेंट के साथ मुस्लिम समुदाय को पॉवरफुल करने का ऐसा एजेंडा शायद अबतक सामने नहीं आया*
2. *यह किताब बहुजन लिबरेशन (मुक्ति) का जैसा परफेक्ट नक्शा पेश करती है, वैसा अबतक देखने में नहीं आया है और*
3. *यूनिवर्सल रिजर्वेशन फ्रंट के जरिए पहली बार भारत की राजनीति में बहुजन लेखक अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हुऐ नजर आएंगे!*

(फ्रैंक हुजूर 'इमरान वर्सेज इमरान : द अनओल्ड स्टोरी', 'सोहो', 'हिटलर इन लव विद मैडोना' जैसी विश्वविख्यात किताबों के लेखक हैं।)

लेखकीय

आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारा संकल्प!

15 अगस्त, 2022 को भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे हुए। इसे यादगार बनाने के लिए पर मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस अवसर को खास बनाने के लिए घर-घर तिरंगा फहराया गया। इस दिन प्रधानमंत्री ने 76 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाने के लिए पंच-प्रण अर्थात पांच संकल्प लिया। कुल मिलाकर आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा शानदार आयोजन रहा, जो लम्बे समय तक देशवासियों की स्मृति में रहेगा। सवाल पैदा होता है क्या आजादी का भव्य अमृत महोत्सव बहुजनों के लिए भी था? बहरहाल 15 अगस्त, 2023 तक चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव का मकसद विगत 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, युवा पीढ़ी को यह बताने का माध्यम बनाना है! इस को स्वाधीन भारत के 75 वर्षों में मिली उपलब्धियां गिनाने का जो माध्यम बनाया गया है, उन उपलब्धियों गिनाने के पहले ध्यान रहे कि 75 साल पूर्व आज ही के दिन भारत के लोग विदेशियों की हजारों साल लम्बी गुलामी झेलकर आज़ाद हुये थे। 1947 के 15 अगस्त का वह दिन था भारत के नवनिर्माण का हर प्रकार की विषमता से पार पाने और आज़ादी का सुफल अर्थात अमृत विभिन्न वर्गों के मध्य बांटने का संकल्प लेने तथा उस संकल्प को पूरा करने का। इस विषय में 'आज़ादी के बाद का भारत' नामक ग्रंथ में सुप्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र-मृदुला मुखर्जी-आदित्य मुखर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है।

आजादी के बाद का भारत का सपना!

उन्होंने लिखा है, 'भारत की आज़ादी इसकी जनता के लिए एक ऐसे युग की शुरुआत थी, जो एक नए दर्शन से अनुप्राणित था। 1947 में देश अपने आर्थिक पिछड़ापन, भयंकर गरीबी, करीब-करीब व्यापक तौर पर फैली महामारी, भीषण सामाजिक विषमता

और अन्याय के उपनिवेशवादी विरासत से उबरने के लिए अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत थी। 15 अगस्त पहला पड़ाव था, यह उपनिवेश राजनीतिक नियंत्रण में पहला विराम था : शताब्दियों के पिछड़ेपन को अब समाप्त किया जाना था, स्वतन्त्रता के वादों को पूरा किया जाना था। भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था तथा राष्ट्रीय राजसत्ता को विकास एवं सामाजिक रूपान्तरण के उपकरण के रूप में विकसित एवं सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण काम था। यह महसूस किया जा रहा था कि भारतीय एकता को आँख मूंदकर मान नहीं लेना चाहिए। इसे मजबूत करने के लिए यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में अत्यधिक क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय एवं धार्मिक विभिन्नताएँ मौजूद हैं। भारत की बहुतेरी अस्मिताओं को स्वीकार करते एवं जगह देते हुये तथा देश के विभिन्न तबकों को भारतीय संघ में पर्याप्त स्थान देकर भारतीयता को और मजबूत किया जाना था।'

आज़ादी के बाद के भारत का चित्र

यह सपना था उस आज़ाद भारत का जिसे 16 अगस्त, 1947 के ही दिन से मूर्त रूप देने में जुट जाना था। पर, आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद क्या हुआ उस सपने का और क्या है उसका वास्तविक चित्र?आज भले ही प्रधानमंत्री मोदी सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता तथा मंगल से लेकर चन्द्रमा तक अपनी छाप छोड़ने का उच्च उद्घोष करें : देश के विश्व आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा करें पर, हाल के वर्षों में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में जो तथ्य उभरकर सामने आये हैं, उनसे पता चलता है कि भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है। ऐसी असमानता विश्व में शायद ही कहीं और हो। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में परम्परागत रूप से सुविधासंपन्न तथा वंचित तबकों के मध्य आर्थिक-राजनीतिक शैक्षिक-धार्मिक और सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में अवसरों के बंटवारे में भारत जैसी असमानता नहीं है। इस असमानता ने देश को 'अतुल्य' और 'बहुजन'-भारत में बांटकर रख दिया है। हाल के वर्षों में प्रकाशित : विश्व असमानता, ऑक्सफाम इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि नीचे की 50-60 प्रतिशत आबादी औसतन 6 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति पर गुजर -बसर करने के लिए अभिशप्त है, जबकि टॉप की 10 प्रतिशत के पास देश की कुल संपत्ति का औसतम 75 प्रतिशत हिस्सा है। भीषणतम आर्थिक और सामाजिक विषमता का सर्वाधिक दुष्परिणाम जिस तबके को भोगना पड़ रहा है, वह है भारत की आधी आबादी! वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम द्वारा 2006 से हर वर्ष जो 'वैश्विक लैंगिक अन्तराल रिपोर्ट' प्रकाशित हो रही है, उसमें साफ़ पता चलता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति करुण से करुणतर हुए जा रही है। ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्टों से पता चलता है कि लैंगिक समानता

के मोर्चे पर पिछड़ते-पिछड़ते भारत आज दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार इत्यादि से भी पीछे चला गया है और यहां की आधी आबादी को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर आने में 257 साल अर्थात अनंत काल लगेंगे।

अभी कुछ दिन पूर्व जब देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी, तभी जुलाई 2022 के तीसरे सप्ताह में 'वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक' से पता चला कि भारत नाइजेरिया के 8,30,05,482 के मुकाबले 8,30,68,597 गरीब पैदा कर विश्व गरीबी की राजधानी (world poverty capital) बन चुका है। इन पंक्तियों के लिखे जाने के दौरान विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत घटिया शिक्षा के मामले में उन 12 देशों की सूची में दूसरे नंबर है, जहाँ दूसरी कक्षा के छात्र एक छोटे से पाठ का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर मलावी नामक एक अज्ञात देश है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत के तीसरी कक्षा के तीन चौथाई छात्र दो अंको के घटाने वाले सवाल को हल नहीं कर सकते, जबकि पांचवी कक्षा के आधे छात्र भी ऐसा नहीं कर पाते!रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल में कई वर्षों बाद भी लाखों बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते या गणित का आसान सवाल हल नहीं कर पाते। रिपोर्ट में ज्ञान के गंभीर संकट को हल करने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने की सिफारिश की गयी है।

आजादी के अमृत में बहुजनों को क्या मिला!

देश की जिस विशाल आबादी को औसतन 6 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति पर गुजर-बसर करना पड़ रहा है; जिस समुदाय की आधी आबादी को आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर आने में 250 से 300 साल लगने हैं : जिनके अर्थाभाव के चलते भारत को गरीबी की राजधानी का ताज मिला है, जिनके बच्चे वर्ल्ड टॉप घटिया शिक्षा के शिकार हैं, वह और कोई नहीं : दलित, आदिवासी, पिछड़ा और इनसे धर्मान्तरित लोगों से युक्त बहुजन समाज है, जिसे आजादी का नाम मात्र ही अमृत मिला है! जिस तरह प्राचीन भारत के देवासुर संग्राम के बाद अमृत का घड़ा देवताओं और विष मूलनिवासीयों को मिला, कुछ वैसी ही स्थिति आजादी के बाद के 75 सालों में रही है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी आजादी के अमृत का वाजिब हिस्सा बहुजनों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को निकटतम भविष्य के मध्य आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे का जो सुझाव दिया था, आजाद भारत के शासक, उसकी बुरी तरह अनदेखी कर दिए। अगर स्वाधीन भारत के हमारे शासक सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे के मोर्चे पर सर्व-शक्ति लगाये होते तो आज़ादी के अमृत का वाजिब हिस्सा बहुजनों को भी नसीब

होता! किन्तु इसके लिए उन्हें शक्ति के स्रोतों-आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक—में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करनी पड़ती अर्थात शक्ति के स्रोतों का सवर्ण, ओबीसी, एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्त्री-पुरुषों के मध्य वाजिब बंटवारा करना पड़ता। लेकिन लोकतन्त्र के ढांचे के विस्फोटित होने की संभावना देखते हुये भी हमारे शासक, जो वर्ण-व्यवस्था के विशेषाधिकारयुक्त व सुविधाभोगी वर्ग से रहे, अपने स्व-वर्णीय/वर्गीय हित के हाथों मजबूर होकर विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा कराने की दिशा में अग्रसर न हो सके। परन्तु शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा न कराने के बावजूद भी 7 अगस्त, 1990 को मण्डल कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के पूर्व तक वे स्वाधीनता संग्राम के वादों को दृष्टिगत रखते हुए भारत के जन्मजात वंचितों के प्रति कुछ-कुछ सदय बने रहे, इसलिए संविधानगत कुछ-कुछ अधिकार देकर शक्ति के स्रोतों में प्रतीकात्मक ही सही, कुछ-कुछ शेयर वंचितों को देते रहे। किन्तु मण्डल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले दिन से वंचितों के प्रति उनकी करुणा, शत्रुता में बदल गई और वे वर्ग-संघर्ष का इकतरफा खेल खेलते हुए शक्ति के स्रोतों से वंचितों को दूर धकेलने के षडयंत्र में लिप्त हो गए।

देवासुर संग्राम से आरक्षण में क्रियाशील : भारत में वर्ग संघर्ष!

मार्क्स ने कहा है अब तक के विद्यमान समाजों का लिखित इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है अर्थात दूसरे शब्दों में जिसका शक्ति के स्रोतों-आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक—पर कब्ज़ा है और दूसरा वह है, जो शारीरिक श्रम पर निर्भर है अर्थात शक्ति के स्रोतों से दूर व बहिष्कृत है। पहला वर्ग सदैव ही दूसरे का शोषण करता रहा है। मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषित : ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे और इनमें कभी भी समझौता नहीं हो सकता। नागर समाज में विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच होने वाली होड़ का विस्तार राज्य तक होता है। प्रभुत्वशाली वर्ग अपने हितों को पूरा करने और दूसरे वर्ग पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए राज्य का उपयोग करता है।'

मार्क्स की वर्ग-संघर्ष के इतिहास की यह व्याख्या एक मानव जाति के सम्पूर्ण इतिहास की निर्भूल व अकाट्य सचाई है, जिससे कोई देश या समाज न तो अछूता रहा है और न आगे रहेगा। जबतक धरती पर मानव जाति का वजूद रहेगा, वर्ग-संघर्ष किसी न किसी रूप में कायम रहेगा। किन्तु भारी अफ़सोस की बात है कि जहां भारत के ज्ञानी-गुनी विशेषाधिकारयुक्त समाज के लोगों ने अपने वर्गीय हित में, वहीं आर्थिक कष्टों के निवारण में न्यूनतम रूचि लेने के कारण बहुजन बुद्धिजीवियों

द्वारा मार्क्स के कालजई वर्ग-संघर्ष सिद्धांत की बुरी तरह अनदेखी की गयी, जोकि हमारी ऐतिहासिक भूल रही। ऐसा इसलिए कि विश्व इतिहास में वर्ग-संघर्ष का सर्वाधिक बलिष्ठ चरित्र हिन्दू धर्म का प्राणाधार उस वर्ण-व्यवस्था में क्रियाशील रहा है, जो मूलतः शक्ति के स्रोतों अर्थात उत्पादन के साधनों के बंटवारे की व्यवस्था रही है एवं जिसके द्वारा ही भारत समाज सदियों से परिचालित होता रहा है। जी हाँ, वर्ण-व्यवस्था मूलतः संपदा-संसाधनों, मार्क्स की भाषा में कहा जाय तो उत्पादन के साधनों के बटवारे की व्यवस्था रही। चूँकि वर्ण-व्यवस्था में विविध वर्णों (सामाजिक समूहों) के पेशे/कर्म तय रहे तथा इन तयशुदा पेशे/कर्मों की विचलनशीलता (Professional mobility) धर्मशास्त्रों द्वारा पूरी तरह निषिद्ध (Prohibited) रही, इसलिए वर्ण-व्यवस्था एक आरक्षण व्यवस्था का रूप ले ली, जिसे हिन्दू आरक्षण कहा जा सकता है। वर्ण-व्यवस्था के प्रवर्तकों द्वारा हिन्दू आरक्षण में शक्ति के समस्त स्रोत सुपरिकल्पित रूप से तीन अल्पजन विशेषाधिकारयुक्त तबकों के मध्य आरक्षित कर दिए गए। इस आरक्षण में बहुजनों के हिस्से में संपदा-संसाधन नहीं, मात्र तीन उच्च वर्णों की सेवा आई, वह भी पारिश्रमिक-रहित। वर्ण-व्यवस्था के इस आरक्षणवादी चरित्र के कारण दो वर्गों का निर्माण हुआ : एक विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न अल्पजन सवर्ण और दूसरा वंचित बहुजन। वर्ण-व्यवस्था में वर्ग-संघर्ष की विद्यमानता को देखते हुए ही 19 वीं सदी में महामना फुले ने वर्ण-व्यवस्था के वंचित शूद्र-अतिशूद्रों को 'बहुजन वर्ग' के रूप में जोड़ने की संकल्पना की, जिसे 20वीं सदी में मान्यवर कांशीराम ने 'बहुजन-समाज' का एक स्वरूप प्रदान किया। बहरहाल प्राचीन काल में शुरू हुए 'देवासुर-संग्राम' से लेकर आज तक बहुजनों की ओर से जो संग्राम चलाये गए हैं, उसका प्रधान लक्ष्य शक्ति के स्रोतों में बहुजनों की वाजिब हिस्सेदारी रही है। वर्ग संघर्ष में यही लक्ष्य दुनिया के दूसरे शोषित-वंचित समुदायों का भी रहा है। भारत के मध्य युग में जहां संत रैदास, कबीर, चोखामेला, तुकाराम इत्यादि संतों ने तो आधुनिक भारत में इस संघर्ष को नेतृत्व दिया फुले-शाहू जी-पेरियार-नारायणा गुरु-संत गाडगे और सर्वोपरी उस आंबेडकर ने, जिनके प्रयासों से वर्णवादी-आरक्षण टूटा और संविधान में आधुनिक आरक्षण का प्रावधान संयोजित हुआ। इसके फलस्वरूप सदियों से बंद शक्ति के स्रोत सर्वस्वहांराओं (एससी/एसटी) के लिए खुल गए।

हजारों साल से भारत के विशेषाधिकारयुक्त जन्मजात सुविधाभोगी और वंचित बहुजन समाज : दो वर्गों के मध्य आरक्षण पर जो अनवरत संघर्ष जारी रहा, उसमें 7 अगस्त, 1990 को मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद एक नया मोड़ आ गया। इसके बाद शुरू हुआ आरक्षण पर संघर्ष का एक नया दौर। मंडलवादी आरक्षण ने परम्परागत सुविधाभोगी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत अवसरों से वंचित एवं राजनीतिक रूप से लाचार समूह में तब्दील कर दिया। मंडलवादी आरक्षण

से हुई इस क्षति की भरपाई ही दरअसल मंडल उत्तरकाल में सुविधाभोगी वर्ग के संघर्ष का प्रधान लक्ष्य था।

मंडलवादी आरक्षण से सुविधाभोगी वर्ग को हुई क्षति की पूर्ति तथा भारत के वंचित बहुजनों को संवैधानिक अवसरों से महरूम करने के लिए नरसिंह राव ने 24 जुलाई, 1991 को अंगीकार किया नवउदरवादी अर्थनीति, जिसे उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं की। किन्तु, इस मामले में किसी ने सबको बौना बनाया तो वह रहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! जिस नवउदारवादी नीति की शुरुआत नरसिंह राव ने किया एवं जिसे भयानक हथियार के रूप इस्तेमाल किया प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने, उसके फलस्वरूप शक्ति के स्रोतों पर भारत के जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग का आज जैसा दबदबा कायम हुआ है, उसकी मिसाल सम्पूर्ण विश्व इतिहास में मिलनी मुश्किल है! शक्ति के स्रोतों पर बेहिसाब कब्ज़ा जमाया भारत का वही जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग ही जूनून के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटा हुआ है। यही वर्ग ही सौ-सौ, दो-दो सौ फुट लम्बा झंडा फहरा रहा है : यही इस अवसर पर नारे लिख रहा है, यही अपने घरों की बालकनी तिरंगे से सजा रहा है।

आज़ादी के अमृत का पूरा घड़ा सुविधाभोगी वर्ग के हाथ में सौपने पर केन्द्रित रही : प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां!

2014 में हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने तीन महीने के अन्दर विदेशों से काला धन लाकर प्रत्येक के खाते में 15 लाख जमा कराने जैसे लोक लुभावन नारे के साथ आंधी-तूफ़ान की तरह केन्द्रीय सत्ता पर काबिज हुए मोदी की नीतियाँ आजादी का समस्त सुफल जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग के हाथ में सौपने पर केन्द्रित रहीं, जिसका सही प्रतिबिम्बन जनवरी, 2018 में आई ऑक्सफाम की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें यह बताया गया था कि देश की सृजित दौलत का 73% हिस्सा टॉप की 1% आबादी वाले अर्थात वर्ण-व्यवस्था के सुविधाभोगी लोगों के हाथ मे चला गया है! यह महज संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से मोदी की नीतियों से ऐसा हुआ था, इसका अनुमान पूर्व की रिर्पोटों से लगाया जा सकता है। पूर्व की रिपोटों के मुताबिक़ 2001 में टॉप के एक प्रतिशत वालों के हाथ में सृजित धन-दौलत का 37 प्रतिशत पहुंचा, जबकि 2005 में बढ़कर 42%, 2010 में 48%, 2012 में 52 % तथा 2016 में 58.5% चली गयी थी। इससे जाहिर है कि 2000 से 2016 अर्थात 16 वर्षों में 1% वालों की दौलत में 21% का इजाफा हुआ, जबकि 2016 से 2017 में 73% प्रतिशत पहुचने का अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष में उनकी दौलत में 15% प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी। है न यह आश्चर्य! यह आश्चर्य इसलिए घटित हुआ क्योंकि

मोदी ने सुविधाभोगी के हाथ में अधिक से अधिक धन-दौलत पहुचाने की नीतियों पर काम किया था। 2018 में ऑक्सफाम की स्तब्धकारी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद बहुत से अखबारों ने लिखा था—'गैर-बराबरी अक्सर समाज में उथल-पुथल की वजह बनती है। सरकार और सियासी पार्टियों को इस समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए। संसाधनों और धन का न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे हो, यह सवाल प्राथमिक महत्त्व का हो गया है।' लेकिन मोदी इन सब बातों से पूरी तरह निर्लिप्त रहे।

2018 के ऑक्सफाम की स्तब्ध कर देने वाली उस रिपोर्ट के बाद स्थिति और बदतर होती गयी और आज टॉप की 10 प्रतिशत आबादी का प्रायः 90 प्रतिशत धन-दौलत पर कब्ज़ा हो गया है। इन टॉप की 10 प्रतिशत आबादी में 99.9 प्रतिशत लोग वर्ण-व्यवस्था के सुवुधाभोगी वर्ग से है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के जन्मजात सुविधाभोगी सवर्ण वर्ग का देश के धन-दौलत पर प्रायः 90 प्रतिशत कब्ज़ा हो चुका है। जिनका धन-दौलत पर प्रायः 90 प्रतिशत कब्जा हो चुका है, उनका सर्विस सेक्टर पर भी जो कब्जा है, उसका ठीक से जायजा लेने पर किसी का भी सिर चकरा जायेगा।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 को जारी आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार में ग्रुप 'ए' की कुल नौकियों की संख्या 84 हजार 521 है। इसमें 57 हजार 202 पर सामान्य वर्गो (सवर्णों) का कब्जा है। यह कुल नौकरियों का 67.66 प्रतिशत होता है। इसका अर्थ है कि 15-16 प्रतिशत सवर्णों ने करीब 68 प्रतिशत ग्रुप ए के पदों पर कब्जा कर रखा है और ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों से युक्त देश की शेष 85 प्रतिशत आबादी के हिस्से में सिर्फ 32 प्रतिशत पद हैं। अब गुप 'बी' के पदों को लेते हैं। इस ग्रुप में 2 लाख 90 हजार 598 पद हैं। इसमें से 1 लाख 80 हजार 130 पदों पर अनारक्षित वर्गों का कब्जा है। यह ग्रुप 'बी' की कुल नौकरियों का 61.98 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि ग्रुप बी के पदों पर भी सर्वण जातियों का ही कब्जा है। यहां भी 85 प्रतिशत आरक्षित संवर्ग के लोगों की सिर्फ 38 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी है। कुछ ज्यादा बेहतर स्थिति ग्रुप 'सी' में भी नहीं है। ग्रुप 'सी' के 28 लाख 33 हजार 696 पदों में से 14 लाख 55 हजार 389 पदों पर अनारक्षित वर्गों (मुख्यतः सवर्णों) का ही कब्जा है। यानी 51.36 प्रतिशत पदों पर। हां, सफाई कर्मचारियों का एक ऐसा संवर्ग है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी 50 प्रतिशत से अधिक है। जहां तक उच्च शिक्षा में नौकरियों का प्रश्न है 2019 के आरटीआई के सूत्रों से पता चला कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफ़ेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पदों पर सवर्णों की उपस्थित क्रमशः 95.2, 92.90 और 76.12 प्रतिशत है।

उपरोक्त आंकड़े 2016 के हैं। जबकि 13 अगस्त, 2019 को संसद में प्रस्तुत

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

• Curate diverse book collections

• Support authors from marginalized communities

• Provide free resources to educators

• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library